(घ) राज्य सरकारों ने 9वीं योजना अवधि के दौरान देश की सभी ग्रामीण बसावटों की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 9149.12 करोड़ रूपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

Employment opportunities in Assam

1674. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for creation of employment opportunities for educated youths in Assam, particularly in its rural, tribal and hill areas;

(b) if so, the details in this regard and if not; the reasons therefor; and

(c) the total amount of expenditure to be incurred on implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOWDA PATIL): (a) to (c) Ministry of Rural areas and Employment is implementing the programmes, namely, Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), Integrated Rural Development Programme (IRDP), Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) for generating employment opportunities in rural areas for people below poverty line throughout the country including tribal and hilly areas of Assam. In addition. Ministry of Industry is implementing Prime Minister Rozgar Yojana (PMRY) for providing job opportunities for educated unemployed youth in rural areas including tribal and hilly areas.

The amount of expenditure incurred on implementation of these Schemes during the current year in Assam are Indicated below:—

(Rs. in lakhs)

Name of the Scheme	Allocation	Expenditure incurred
JRY	8357.73	2735.23
MWS	1808.38	565.64
EAS	10035.00	6043.42
IRDP	10492.72	1027.67
DWCRA	1122.40	66.81
TRYSEM	647.42	49.89
TOOLKITS	424.42	85.08

Under PMRY no State-wise allocation of funds is made.

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु आबंटनों में कटौती

1675. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री कपिल सिब्बल :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष, 1998-99 के बजट में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आबंटनों में कटौती करने केलिए एक निर्णय लिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है,

(ग) कुल आबंटित धनराशि कितनी थी और उसमें से कुल कितनी धनराशि की कटौती करने का निर्माण लिया जा रहा है, और

(घ) दिसम्बर, 1998 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क) से (ग) कुछ कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्य निष्पादन के आधार पर और इन एजेंसियों के पास खर्च न की गई राशि के सग्रंह को देखते हुए आबंटन को 9900 करोड़ रूपये से घटाकर 9400 करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया गया है जिससे ग्रामीण विकास रूपये करने का निर्णय लिया गया है। जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों करने का निर्णय लिया गया है जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आबंटन 500 करोड़ रूपये कम हो जायेगा।

(घ) दिसम्बर, 1998 तक कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 8285.80 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीणों का प्रवास

1676. **श्री मती सरोज दुबे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं,